बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 93 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 20 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली में शराब तस्करों ने पुलिस पर किया हमला, 36 पेटी अवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में चेकिंग के दौरान शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। आई-10 कार सवार तस्करों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। इस दौरान कॉन्स्टेबल मुकेश घायल हो गए। इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को घेरकर दबोच लिया। उनके पास से 36 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंजीत और चांद मोहम्मद के रूप में हुई है। टक्कर लगने से दोनों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत स्थिर है। कार की तलाशी लेने पर उसमें से अवैध शराब बरामद की गई।

हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद न करें, जयशंकर की पोलैंड को दो टूक

नई दिल्ली। भारत और पोलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्री जयशंकर पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के सामने रूस-यूक्रेन युद्ध के नाम पर भारत को चुनिंदा और अनुचित तरीके से निशाना बनाए जाने पर आपत्ति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जयशंकर ने किस्तान का नाम लिए बिना कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पोलैंड को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनानी चाहिए और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं देना चाहिए। जयशंकर ने नई दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ अपनी मुलाकात के दौरान भारत की चिंताओं को उठाया। इस दौरान दोनों देशों ने भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी के विस्तार की समीक्षा की और प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। पोलिश प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह बैठक वैश्विक मामलों में काफी उथल-पुथल के दौर में हो रही है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के देशों के लिए विचारों का आदान-प्रदान करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जयशंकर ने

इस बात पर जोर दिया कि भारत और पोलैंड, जिनके संबंध अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वारसॉ यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे थे। कार्य योजना 2024-28 की समीक्षा करेंगे और व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में गहन सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएंगे। लेकिन यह बातचीत जल्द ही भू-राजनीति, विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष और उसके व्यापक प्रभावों की ओर मुड़ गई। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने न्यूयॉर्क और पेरिस सहित कई मौकों पर मंत्री सिकोरस्की के साथ भारत के विचारों को स्पष्ट रूप से साझा किया था और नई दिल्ली में भी उन्हें दोहराया। जयशंकर ने आगे कहा कि ऐसा करते हुए मैंने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मैं आज फिर से यही बात दोहराता हूं। भारत ने यह बार-बार स्पष्ट किया है कि वह संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति चाहता है और चुनिंदा लक्ष्यों को निशाना बनाकर किसी गुट विशेष के पक्ष में जाने से खुद को रोकता है। पोलैंड के मंत्री सिकोरस्की ने भी मोटे तौर पर भारत की चिंताओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पोलैंड भी चुनिंदा लक्ष्यों को निशाना बनाने की अनुचितता से सहमत है और चेतावनी दी कि ऐसी प्रथाओं से वैश्विक व्यापार में व्यापक उथल-पुथल मच सकती है।

अपने देश में हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पोलैंड आगजनी और राय आतंकवाद के प्रयासों का शिकार रहा है, जिसमें रेलवे लाइन पर हमला भी शामिल है। पोलैंने के मंत्री ने आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

दिल्ली में सियासी हलचल तेज, बीजेपी का आप से सवाल- आतिशी को क्यों छुपाया जा रहा है?

नई दिल्ली । दिल्ली की सियासत में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. दिल्ली बीजेपी के महामंत्री एवं सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना को जानबूझकर जनता और मीडिया से दूर रखा गया है.

बीजेपीने इसे सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़े मुद्दे से जोड़ते हुए आप नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है. दिल्ली बीजेपीके महामंत्री एवं सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के साथ एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी यह बताए कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुश्री आतिशी मार्लेना को आखिर कहां छुपा कर रखा गया है. सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि क नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि आतिशी मार्लेना ने सिखों के गुरु साहिबान के प्रति कोई बेअदबी नहीं की. उन्होंने सवाल किया कि यदि ऐसा ही है तो 6 जनवरी की शाम से उन्हें दिल्ली की जनता और मीडिया से दूर क्यों रखा गया है. बीजेपी सांसद ने कहा कि 7 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने विधानसभाध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो पर आपत्ति जताते हुए उसकी जांच की मांग की थी. लेकिन कुछ ही घंटों में आप नेतृत्व अपने ही विधायकों की बात से मुकर गया और पंजाब में एफआईआर दर्ज कर एक ही दिन में जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी गई. चांदोलिया ने सवाल किया कि यदि दिल्ली विधानसभा में हुई घटना पर आप को आपत्ति थी तो उसकी एफआईआर दिल्ली में दर्ज क्यों नहीं कराई गई. उन्होंने इसे पूरे मामले को दबाने की कोशिश करार दिया. दिल्ली बीजेपीसांसद ने आरोप लगाया कि अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान भी उतने ही दोषी हैं जितनी आतिशी मार्लेना. उन्होंने कहा कि सिख गुरु साहिबान के अपमान के मुद्दे पर आप नेतृत्व जवाब देने से बच रहा है और सच सामने आने से डर रहा है. यह मामला दिल्ली की राजनीति में नया मोर्चा खोल सकता है और आप के लिए चुनौती बन सकता है.

कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण का कहर, गंभीर श्रेणी में फिजा, कई इलाकों में 450 पार एक्यूआई

नई दिल्ली ।

राजधानी में पारा गिरने और खराब मौसम की स्थिति ने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया है। सोमवार सुबह को भी हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई। इसके चलते कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। गंभीर प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या हुई। यही नहीं, सड़कों पर लोग मास्क पहने हुए दिखे। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 418 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के अलीपुर में 395, आनंद विहार में 462, अशोक विहार में 473, आया नगर में 340, बवाना में 448, बुराड़ी में 460, और चांदनी चौक इलाके में 454 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं, डीटीयू इलाके में 467, द्वारका सेक्टर-8 में 427, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 में 340, आईटीओ में 431, लोधी रोड में 382, मुंडका में 467, नजफगढ़ में 346, नरेला में 437, पंजाबी बाग में 434, आरकेपुरम में 439, रोहिणी में 471, सोनिया विहार में 469, विवेक विहार में 472 और वजीरपुर में 472 एक्यूआई दर्ज किया गया है। इसके अलावा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शनिवार देर रात को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप)-4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। ऐसे में राजधानी में अब ग्रेप के सारे चरण लागू हैं। इन चरण के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए 5-पॉइंट एक्शन प्लान को सख्ती से लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बनी हुई गंभीर वायु गुणवत्ता का मुख्य कारण मौसम का मिजाज है। ऐसे में तापमान में कमी के कारण प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि हुई है और पश्चिमी विक्षोभ के चलते वायु गुणवत्ता जो नीचे फंसी हुई ठंडी हवा को ऊपर उठने नहीं देती है। इसी ठंडी हवा में गाड़ियों का धुआं और निर्माण की धूल जैसे प्रदूषक जमा हो जाते हैं। प्रदूषकों को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वे जमीन के बहुत करीब फंसे रहते हैं। साथ ही, जब बारिश नहीं होती और हवा भी धीरे चलती है, तो यह फंसा हुआ प्रदूषण बाहर नहीं निकल पाता, जिससे स्थिति कई गुना खराब हो जाती है।

विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- मुकदमा चलाने की मंजूरी देनी है या नहीं

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करें। यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनके आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी है। अब राय सरकार की मंजूरी का इंतजार है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (साम्प्रदायिक नफरत फैलाना) के तहत कार्रवाई के लिए जरूरी है। एसआईटी ने शाह के अन्य कथित आपत्तिजनक बयानों का भी हवाला दिया है और कोर्ट ने इसके लिए भी रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में शाह के वरिष्ठ वकील ने कहा कि शाह ने अपनी माफी दर्ज कराई है और जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने माफी को रिकॉर्ड पर स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह बहुत देर से दी गई है। इससे पहले, कोर्ट ने उनकी सार्वजनिक माफी को घड़ियाली आंसू बताते हुए इसे कानूनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका माना था। गौरतलब है कि यह मामला ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठकर सामने आया, जब शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने उनके बयानों की निंदा करते हुए स्वतंत्र जांच के आदेश दिए और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में आज शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई होगी। मजीठिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें असमान संपत्ति मामले में जमानत नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा और तय करेगा कि क्या उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला नेताओं की संपत्ति और जवाबदेही के संबंध में अहम माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध की जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने की प्रक्रिया से जुड़ी एक अहम याचिका को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह याचिका केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से इस विषय पर एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग करती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीएस येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और आज कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा।वहीं चुनाव आयोग से जुड़ा है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के सारांश संशोधन प्रक्रिया को चुनौती दी है, जिसके तहत निर्वाचन रजिस्टर में सुधार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आज इस याचिका पर भी विचार करेगा।

दिल्ली एमएसीटी का बड़ा फैसला: हादसे में घायल छात्र को 1.62 करोड़ का मुआवजा, बीमा कंपनी को देनी होगी राशि

बाहरी दिल्ली। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को 1.62 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई, जिसके लिए बीमा कंपनी को पूरी राशि अदा करनी होगी। मामला एक जुलाई 2024 का है। 21 वर्षीय छात्र आर्यन राणा स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में आर्यन को गंभीर चोटें आई और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेडिकल जांच में उन्हें 53 फीसदी दिव्यांग घोषित किया गया। वहीं, सुनवाई के दौरान बस चालक व अन्य प्रतिवादियों ने खुद को झूठा फंसाए जाने का दावा किया, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस शिकायत या साक्ष्य पेश नहीं किया गया। पीठासीन अधिकारी विक्रम ने चश्मदीद गवाहों और बस कंडक्टर के बयानों के आधार पर स्पष्ट किया कि बस ओवरटेक करने के प्रयास में स्कूटी से टकराई, जो चालक की लापरवाही को साबित करता है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हादसे के समय आर्यन प्रथम वर्ष के होनहार छात्र थे, लेकिन इस दुर्घटना के बाद उनकी कार्यक्षमता पर गहरा असर पड़ा है। भले ही चिकित्सकीय रूप से दिव्यांगता 53 प्रतिशत आंकी गई, लेकिन भविष्य में रोजगार और आजीविका की दृष्टि से उनकी कार्यक्षमता में 90 फीसदी तक कमी मानी गई। अदालत ने विभिन्न मदों के तहत कुल 1.62 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा तय किया, जिसमें 59.36 लाख रुपये भविष्य की आय के नुकसान के लिए निर्धारित किए गए हैं।

प्लास्टिक नियम तोड़ने पर 85 कंपनियों को नोटिस, दिल्ली सरकार ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली। राजधानी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध है और बिना प्रमाणित बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बेचना गैरकानूनी है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने पर 85 कंपनियों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। यह खुलासा दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी अपनी रिपोर्ट में किया है। इसमें बताया गया है कि प्लास्टिक कचरे के सही निपटान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली सरकार गंभीर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2022 में लागू किए गए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) नियमों के तहत प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपने प्लास्टिक कचरे की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। इसी तरह, प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस करने वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इन नियमों से प्लास्टिक कचरे पर बेहतर नियंत्रण संभव हुआ है। यह हलफनामा एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में दिया गया है, जिसमें यह दावा किया गया था कि राजधानी में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा गायब हो रहा है। सरकार का कहना है कि प्लास्टिक कचरे को लेकर नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के निदेशक निगम अग्रवाल ने रिपोर्ट में बताया है कि सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे में दिल्ली में अब तक 2386 पीआईबीओ और 494 पीडब्ल्यूपी ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। इनमें से 2264 पीआईबीओ और 422 पीडब्ल्यूपी को मंजूरी मिल चुकी है।

जागरूकता बढ़ाने के लिए अखबारों में नोटिस जारी

रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने कंपनियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अखबारों में नोटिस जारी किए। इसमें औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वे कराए, इंडस्ट्री एसोसिएशनों के साथ बैठकें कीं और निरीक्षण भी किए। यही नहीं, रिपोर्ट में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी रजिस्टर्ड कंपनियों को 30 नवंबर 2025 तक अपना सालाना रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसा न करने पर सिस्टम अपने आप रिटर्न तैयार करेगा, अगले साल का लक्ष्य 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कुल मिलाकर ढाई लाख टन से यादा प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए रिसाइक्लिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईपीआर पोर्टल अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। तब से दिल्ली में पीआईबीओ और पीडब्ल्यूपी की हजारों एप्लीकेशन आईं। ज्यादातर को मंजूरी मिल गई, लेकिन कुछ रिजेक्ट हुईं।

योग और स्वस्थ

भारत की प्राचीन सभ्यता में योग को जीवन का आधार माना गया है। आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण दुनिया में जहां जीवनशैली संबंधी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और मानसिक विकार तेजी से बढ़ रहे हैं, योग एक प्राचीन लेकिन अत्यंत प्रासंगिक समाधान के रूप में उभर रहा है। भारत की यह अमूल्य धरोहर न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है, बल्कि मन की शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करती है। बीते वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' ने इसे और अधिक प्रासंगिक बना दिया है, क्योंकि योग व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरणीय संतुलन तक सब कुछ जोड़ता है। आज का विषय योग को दैनिक जीवन में अपनाने के व्यावहारिक लाभों पर केंद्रित है, ताकि हम एक स्वस्थ, सकारात्मक और संतुलित जीवन जी सकें। योग का अर्थ है "जोड़ना" या "मिलन"। यह शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में योग को 'चित्त वृत्ति निरोधः' कहा गया है, अर्थात मन की वृत्तियों का निरोध लेकिन योग सिर्फ ध्यान या समाधि तक सीमित नहीं, यह हठ योग, राज योग, भक्ति योग और कर्म योग जैसे विभिन्न रूपों में जीवन को संतुलित करता है। आज के संदर्भ में, हठ योग के आसन और प्राणायाम सबसे अधिक प्रचलित हैं, क्योंकि ये व्यावहारिक और तुरंत लाभ देने वाले हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग के लाभ अनेक हैं। नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला, मजबूत और संतुलित होता है। सूर्य नमस्कार जैसे गतिशील आसन पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं, रक्त संचार बढ़ाते हैं और चयापचय (मेटाबॉलिज्म) को तेज करते हैं। इससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। कई अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि योग से मोटापा कम होता है, खासकर पेट की चर्बी। धनुरासन, भुजंगासन और नौकासन जैसे आसन पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत देते हैं। महिलाओं के लिए योग मासिक धर्म चक्र को नियमित करता है, प्रसव के बाद रिकवरी में सहायक होता है और हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी वृद्धावस्था की बीमारियों से बचाव होता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए योग एक वरदान है। अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करते हैं और हृदय की धड़कन को संतुलित रखते हैं। भारत में हृदय रोग मौत का प्रमुख कारण है और योग जैसे प्राकृतिक तरीके से इसे रोका जा सकता है। योग इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोविड महामारी के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मानसिक स्वास्थ्य योग का सबसे बड़ा योगदान है। आज की युवा पीढ़ी चिंता, अवसाद और तनाव से ग्रस्त है। योग में ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करते हैं। विपश्यना या mindfulness ध्यान से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, नींद बेहतर आती है और एकाग्रता बढ़ती है। छात्रों के लिए यह परीक्षा तनाव कम करने का बेहतरीन माध्यम है। कार्यरत लोगों के लिए योग वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। योग से आत्मविश्वास बढ़ता है जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी है। योग को स्वस्थ जीवनशैली का आधार बनाना चाहिए। योग सिर्फ आसन नहीं, बल्कि आहार, नींद और दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। आयुर्वेद के अनुसार, सात्विक भोजन (फल, सब्जियां, दालें, अनाज और दूध) योग के लाभों को बढ़ाता है। जंक फूड, ज्यादा तेल-मसाले और रात में भारी भोजन से दूर रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय के साथ योग करना और रात को 7-8 घंटे की नींद लेना आदर्श है। डिजिटल डिटॉक्स भी योग का हिस्सा बन सकता है-स्क्रीन टाइम कम करके ध्यान बढ़ाना। योग नियमित अभ्यास से लचीलापन बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और संतुलन सुधारता है जिससे गिरने का खतरा कम होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध है कि यह तनाव कम करता है, कोर्टिसोल स्तर घटाता है और चिंता को 40% तक कम कर सकता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर नींद, आत्मसम्मान में वृद्धि और समग्र जीवन गुणवत्ता में वृद्धि जैसे लाभ भी प्रमाणित हैं। योग कैंसर रोगियों में थकान कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है जिससे दैनिक जीवन अधिक संतुलित और ऊर्जावान बनता है। सामाजिक स्तर पर योग समुदाय को जोड़ता है। गांवों में योग शिविर, शहरों में पार्कों में सामूहिक सत्र और स्कूलों में योग शिक्षा से लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं। महिलाओं के लिए यह सशक्तिकरण का साधन है-घरेलू कामों के साथ स्वास्थ्य बनाए रखना। बुजुर्गों के लिए योग गतिशीलता बनाए रखता है और अकेलेपन को कम करता है। पर्यावरणीय दृष्टि से, योग हमें प्रकृति से जोड़ता है। योग हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पृथ्वी का स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। कम खपत, अधिक जागरूकता और संतुलित जीवन से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।

आर्थिक रूप से भी योग फायदेमंद है। अस्पतालों के खर्च कम होते हैं, दवाओं पर निर्भरता घटती है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है जिससे परिवार और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। भारत में योग पर्यटन बढ़ रहा है-ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे स्थान विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते है जिससे रोजगार भी बढ़ता है। योग अपनाना आसान है। शुरुआत में 15-20 मिनट रोज काफी है। घर पर ऑनलाइन वीडियो या ऐप्स से सीख सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाएं जैसे आयुष मंत्रालय के योग कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शिविर मुफ्त प्रशिक्षण देते हैं लेकिन महत्वपूर्ण है निरंतरता। योग कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है। योग को धीरे-धीरे बढ़ाएं, शरीर की सुनें और धैर्य रखें। याद रहे कि योग हमें सिखाता है कि सच्चा स्वास्थ्य बाहर नहीं, भीतर है। जब हम योग अपनाते हैं तो न केवल हम स्वस्थ होते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण भी लाभान्वित होता है। इसलिए कोशिश करें कि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

तेजी से बदलता 'महाराष्ट्र'

पिछले दो दशकों में देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की राजनीति में जो गुणात्मक परिवर्तन गांवों से लेकर शहरों तक में आया है उससे भारतीय जनता पार्टी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का अन्दाजा आसानी से हो सकता है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में भारतीय जनाता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी मगर बाद में इसी वर्ष में हुए विधानसभा चुनावों में इस पार्टी ने सभी पुराने रिकार्ड तोड़ते हुए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। भाजपा ने यह सफलता एक समय में राज्य में सबसे मजबूत मानी जाने वाली पार्टी कांग्रेस की कीमत पर हासिल की है। इससे राज्य भर में कांग्रेस पार्टी अब हाशिये पर जाती दिखाई पड़ रही है परन्तु इस पार्टी की जड़ें अभी तक राज्य के गांवों से लेकर शहरों तक में फैली हुई हैं और इसकी विरासत काफी विस्तृत मानी जाती है जिसकी वजह से यह यदा-कदा चुनावों में आंचलिक स्तर पर चमत्कार भी पैदा कर देती है। हाल में सम्पन्न महाराष्ट्र राज्य के 29 नगर निगम (मुम्बई समेत) चुनावों में भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी दलों को 23 शहरों में सफलता प्राप्त हुई है परन्तु कांग्रेस पार्टी भी अपने बूते पर दो शहरों भिवंडी व लातूर में अपना बहुमत कायम रखने में कामयाब हो गई है किन्तु इस राज्य से 1999 के करीब कांग्रेस से अलग हुई श्री शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस का अब लगभग सफाया हो गया है और इसके साथ ही राज्य की दूसरे नम्बर की सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाली पार्टी शिवसेना के लिए भी मुम्बई को छोड़ कर शेष राज्य में अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक ग्राफ बहुत उतार-चढ़ाव वाला भी रहा है परन्तु 90 के दशक से इसने शिवसेना के साथ गठबन्धन करके अपनी ताकत में इजाफा करना शुरू किया और अपनी हिन्दुत्ववादी राजनीति का विस्तार भी शिवसेना की कीमत पर भी किया। शिवसेना के प्रभाव में 80 के दशक से राज्य भर में विस्तार होना शुरू हुआ जिसकी शुरूआत मुम्बई नगर निगम से ही हुई। इसके बाद इस पार्टी का राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी इसकी मराठी अस्मिता की राजनीति ने असर दिखाना शुरू किया और मराठी मानुस व हिन्दुत्व इसके मूल मन्त्र बनते गये। भाजपा ने इसी पार्टी के साथ गठबन्धन करके हिन्दुत्व के राष्ट्रीय फलक को महाराष्ट्र में उतारा और अपने प्रभाव में विस्तार किया। इस बहाने शिवसेना के साथ-साथ भाजपा भी राज्य के गांवों तक पहुंची। वरना 70 के दशक तक यह पार्टी राज्य में उत्तर भारत की पार्टी कहलाती थी और उस नागपुर इलाके से भी सरती रहती थी जहां शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय विद्यमान है। परन्तु 90 के दशक के आते-आते इसमें आधारभूत परिवर्तन आना शुरू हुआ जिसमें 1986 से शुरू हुए अयोध्या में श्री राम मन्दिर निर्माण आन्दोलन की भी प्रमुख भूमिका रही। इस आन्दोलन का उस समय शिवसेना ने भी खुलकर समर्थन किया था और आन्दोलन को उग्र तेवर तक बख्शे थे। शिवसेना के संस्थापक स्व . बाला साहेब ठाकरे ने राम मन्दिर आन्दोलन में अपने स्वयंसेवकों की काफी बड़ी फौज भी भेजी थी। मगर इस आन्दोलन की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी और इसके तत्कालीन नेता श्री लाल कृष्ण अडवानी इसका नेतृत्व कर रहे थे। अतः महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी राज्य में भाजपा को अपना विस्तार करने में सुविधा हुई। इससे पहले जब 1967 में पूरे देश में गैर कांग्रेसवाद की लहर चली थी तो भाजपा (जनसंघ) केवल उत्तर भारत के राज्यों तक ही सीमित होकर रह गई थी हालांकि इस वर्ष देश के नौ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का पहली बार गठन हुआ था।

महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 47 सीटें कांग्रेस के पास रही थी और राज्य विधानसभा में इसका दो-तिहाई बहुमत आया था। मगर 70 के दशक के बाद से इसमें कमी दर्ज होनी शुरू हुई जिसकी वजह मूल रूप से शिवसेना ही थी क्योंकि इसने अपनी उग्र हिन्दुत्व व मराठी अस्मिता की राजनीति को राज्य के मराठी मानुस तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। भाजपा के 90 के दशक से इसके साथ सहयोग से राज्य में कांग्रेस का प्रभुत्व घटने लगा और 80 के दशक के उत्तरार्ध में भाजपा के राष्ट्रीय फलक पर चमकने से राष्ट्रीय लोकसभा चुनावों व विधानसभा चुनावों में भी शिवसेना के साथ इसे अच्छी सफलता मिलने लगी। दोनों पार्टियों के बीच यह मेलजोल 2019 तक बना रहा मगर इस वर्ष हुए चुनावों के बाद मुख्यमन्त्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तकरार हो गई और शिवसेना ने भाजपा के साथ अपना गठबन्धन तोड़ दिया और उस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया जिसके विरुद्ध वह अपने जन्मकाल से ही संघर्ष करती आ रही थी। इससे शिवसेना के उस सैद्धान्तिक पक्ष को गहरा धक्का लगा जिसे सामने रखकर वह मराठियों से वोट मांगा करती थी। हकीकत यह थी कि 2019 का विधानसभा चुनाव शिवसेना व भाजपा दोनों ने साथ मिल कर ही लड़ा था और मतदाताओं ने इस गठबन्धन को पूर्ण बहुमत भी दिया था जिसमें भाजपा विधायकों की संख्या शिवसेना के विधायकों से ज्यादा थी परन्तु शिवसेना मुख्यमन्त्री पद अपने पास ही रखना चाहती थी और इसी लालच में इसने गठबन्धन तोड़कर कांग्रेस व शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिला कर अपने नेता उद्धव ठाकरे को मुख्यमन्त्री बना दिया इससे शिवसेना के हाथ में सत्ता तो आ गई मगर उसका जनाधार खिसकियां भरने लगा जिसे 2022 में इसी पार्टी के नेता एकनाथ शिन्दे ने तोड़ लिया और शिवसेना में विद्रोह करके अपनी अलग शिवसेना बना ली। 2022 के बाद महाराष्ट्र में जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी में शिन्दे की शिवसेना को बेहतर सफलता प्राप्त हुई है। शिन्दे ने रणनीतिक रूप से भाजपा से गठबन्धन किया और बाला साहेब ठाकरे की सैद्धान्तिक राजनीति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जिसमें उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। मगर इस उठा-पटक में कांग्रेस व शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज्यभर से अपना अस्तित्व खोती जा रही है जिसे भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से भरती जा रही है।

सम्पादकीय...

'लालकिला' के वारिस

भारत के अंतिम मुगल शहंशाह एवं प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रथम पुरुष सम्राट बहादुर शाह जफर के वंशज अब एक साधारण जिंदगी जीने पर विवश है। अपने समय के इस महान शायर एवं मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चिराग के कुछ वंशज अब रंगून (म्यांमार, तब बर्मा) में रहते हैं और कुछ कोलकाता में एक स्टॉल लगाकर चाय बेचते हैं। सन् 1857 की क्रांति के मध्य बहादुरशाह जफर को अंग्रेजी सेनाओं ने लालकिला से गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुकदमा भी चला और बाद में उन्हें देश-निर्वासन का दण्ड देकर रंगून (म्यांमार) भेज दिया गया था, जहां दवा-दारू व देखभाल के अभाव में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। वहां उनकी उपेक्षित कब्र भी है जहां स्वतंत्र भारत के अनेक नेताओं ने अपने श्रद्धासुमन भी अपनी रंगून-यात्रा के मध्य चढ़ाए हैं। मगर पाकिस्तान या बंगलादेश का कोई नेता कभी वहां नहीं गया। 1847 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद उनके दो बेटों को बिना मुकदमा चलाए ही फांसी दे दी गई थी। इनमें वली अहद (युवराज) मिर्जा मुगल भी थे। जफर के साथ उनके बेटे मिर्जा जवान बख्त और उनकी पत्नी जीनत महल और पोते शाह अब्बास भी रंगून गए। शाह अब्बास ने वहीं शादी की और उनके वंशज आज भी म्यांमार में रहते हैं लेकिन वे सामान्य एवं नौकरी पेशा जीवन जीते हैं। कुछ वंशज भारत में भी हैं जो साधारण जीवन यापन करते हैं, जैसे कि टी स्टॉल लगाकर चाय बेचना। मुगल साम्राज्य भले ही खत्म हो गया लेकिन बहादुर शाह जफर की विरासत, खासकर उनकी उर्दू शायरी एवं गजलों के रूप में आज भी जीवित है। कई लोग उनकी कब्र (जो रंगून में है) पर जाते हैं। उनके वंशज अब राजा या शासक नहीं बल्कि आम लोग हैं लेकिन मुगल इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके एक प्रपौत्र बेदार बख्त का परिवार इन दिनों हावड़ा के शिवपुरी इलाके की एक तंग गली में रहता है। हाल ही में परिवार की एक प्रपौत्र वधु का एक वक्तव्य मीडियाई चर्चा में आया है। 'मेरा नाम रजिया सुल्ताना बेगम है। मैं मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह शाह जफर के पड़पोते मिर्जा बेदार बख्त की पत्नी हूं। 15 अगस्त, 1965 को मेरी शादी हुई थी। आज मेरी जिंदगी हावड़ा के शिवपुरी इलाके की एक तंग गली में सिमटकर रह गई है। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ीं लेकिन आमदनी नहीं। पति को शाही शौक थे, मगर जेब खाली रहती थी। मैंने जिल्द बांधने, लाख की चूड़ियां बनाने, बिल वाले पेन के रीफिल लगाने जैसे काम किए। उनके निधन के बाद हालात और बदतर हो गए। कई-कई दिन ऐसे आए जब बच्चों को सिर्फ पानी और सूखी ब्रेड मिली। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज भी दर्द तब और गहरा हो जाता है जब मैं दिल्ली जाकर अपने ही इतिहास को देखने के लिए टिकट खरीदती हूं। लाल किला जाने के लिए 50 रुपए और हुमायूं का मकबरा देखने के लिए 40 रुपए देने पड़ते हैं जबकि ये सब मेरे ही खानदान की विरासत हैं। मेरे पति की मौत पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था लेकिन उसके बाद जिंदगी ने कोई इज्जत नहीं दी। बाद में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पेंशन बढ़ाई थी मगर वह किराए और इलाज में खत्म हो जाती है। मेरा एक ही सवाल है, 'अगर मुगल शहंशाह जफर गद्दार नहीं थे तो उनके वंशज आज बेघर क्यों हैं? यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि उस दर्द की दास्तान है जिसमें शाही अतीत और भूख से भरा वर्तमान आमने-सामने खड़ा है। जफर की आखिरी इच्छा भी अधूरी ही रही।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन कर धारा 17-ए जोड़ी गई हैं

वैश्विक स्तरपर भारत जब अपनी आजादी के सौ वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, तब विजन 2047 के तहत एक ऐसा राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है जहाँ भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता केवल नारा नहीं, बल्कि शासन का मूल चरित्र हो। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में नीतिगत संकल्प तभी सफल होते हैं, जब उन्हें लागू करने वाले कानूनी ढाँचे में विरोधाभास न हों।आज भारत में यही विरोधाभास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के रूप में सामने खड़ा है, जो एक ओर ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा का दावा करती है,तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार- मुक्त शासन के लक्ष्य को कमजोर करती प्रतीत होती है।मैं एडवोकेट किशन भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए केवल आर्थिक नुकसान का कारण नहीं होता,बल्कि यह जनता केविश्वास संस्थाओं की साख और कानून के राज को भीतर से खोखला कर देता है। विश्व बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच बार-बार यह रेखांकित कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार सीधे तौर पर गरीबी, असमानता और सामाजिक अशांति को बढ़ाता है।

भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में,जहाँ करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं और निर्णयों पर निर्भर हैं, वहाँ भ्रष्टाचार का प्रभाव और भी विनाशकारी हो जाता है।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को इसी पृष्ठभूमि में बनाया गया था। इसका मूलउद्देश्य था लोकसेवकों को जवाबदेह बनाना रिश्वत,पद के दुरुपयोग और सत्ता के दुराचार को आपराधिक कृत्य घोषित करना,जनता के संसाधनों और अधिकारों की संवैधानिक रक्षा करना।इस अधिनियम की आत्मा यह मानकर चलती थी कि लोकसेवक का पद एक ट्रस्ट है, न कि विशेषाधिकार।वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसके तहत धारा 17-ए जोड़ी गई। इस धारा के अनुसार, किसी भी लोकसेवक के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णयों या की गई सिफारिशों के संबंध में बिना पूर्व अनुमति कोई जांच, पूछताछ या एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती,यह अनुमति संबंधित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जानी होती है।सरकार का तर्क है कि हर दिन अधिकारी ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ता है,हर निर्णय सभी को पसंद नहीं आता,यदि हर असंतुष्ट व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सके, तो इससे प्रशासन ठप हो जाएगा।अधिकारी भय के माहौल में काम करेंगे, जिससे विकास की गति धीमी होगी।सरकार के अनुसार, धारा 17-ए ईमानदार अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने की एक आवश्यक ढाल है।लेकिन मूल प्रश्न- क्या सुरक्षा के नाम पर जांच पर ताला?यहीं से विवाद शुरू होता है। लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वतंत्रता होती है। यदि जांच शुरू करने के लिए भी उसी शासन से अनुमति लेनी पड़े, जिसके खिलाफ जांच संभावित है, जिसकी नीतियों और फैसलों में भ्रष्टाचार की आशंका है,तो क्या यह व्यवस्था जांच को निष्पक्ष बना सकती है?आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान जांच एजेंसियों को नाममात्र की स्वतंत्रता देता है और उन्हें कार्यपालिका के अधीन कर देता है।

साथियों बात कर हम नीतिगत भ्रष्टाचार-सबसे बड़ा और सबसे अदृश्य खतरा इसको समझने की करें तो भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने तक सीमित नहीं है। आधुनिक लोकतंत्रों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नीतिगत फैसलों में होता है, टेंडर और ठेके,लाइसेंस और अनुमति,खनन, भूमि, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ,रक्षा और सार्वजनिक खरीद यदि इन्हीं फैसलों को जांच से बाहर कर दिया जाए, तो भ्रष्टाचार कानून का अस्तित्व ही निरर्थक हो जाता है।

राजनीतिक संरक्षण और हितों का टकराव-धारा 17-ए का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह राजनीतिक संरक्षण को संस्थागत रूप दे सकती है। यदि किसी मामले में सरकार स्वयं शामिल हो,या उच्च स्तर पर मिलीभगत हो,तो अनुमति मिलने की संभावना न के बराबर रह जाती है। यह स्थिति हितों के टकराव का क्लासिक उदाहरण है। साथियों बात अगर हम सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को समझने की करें तो इसी चिंता को लेकर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस17 ए धारा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (न्यायपूर्ण प्रक्रिया) के खिलाफ है।यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है।जांच में देरी से साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं,गवाह प्रभावित हो सकते हैं।

भ्रष्टाचार के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है।जैसे-जैसे समय बीतता है,फाइलें बदली जा सकती हैं दस्तावेज गायब हो सकते हैं,डिजिटल सबूत मिटाए जा सकते हैं,गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है।यदि जांच शुरू होने में ही महीनों लग जाएं, तो सच्चाई तक पहुँचना लगभग असंभव हो जाता है।

शिकायत करने वाले के भीतर डर का माहौल पैदा किया जाता है तो ईमानदार नागरिक भी चुप हो जाता है,इस कानून का एक अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा प्रभाव यह भी है कि,ईमानदार अधिकारी, पत्रकार,सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ शिकायत करने से पहले सौ बार सोचने लगते हैं।यह स्थिति व्हिसलब्लोअर संस्कृति को खत्म कर देती है, जो किसी भी पारदर्शी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। साथियों बात अगर हम 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में खंडित फैसला सुनाए जाने को समझने की करें तो,एक माननीय जस्टिस ने धारा 17-ए को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की राय दी।जबकि दूसरे माननीय जस्टिस ने इसे ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हुए वैध ठहराया लेकिन लोकपाल/लोकायुक्त की भूमिका के साथ।यह विभाजन अपने आप में बताता है कि यह मुद्दा कितना जटिल और संवेदनशील है।जब सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की राय अलग-अलग होती है, तो मामला चीफ जस्टिस के पास जाता है। अब यह विषय बड़ी पीठ तय करेगी किसंविधान का कौन-सा पक्ष अधिक मजबूत है,और लोकतंत्र की दीर्घकालिक जरूरत क्या है।

साथियों बात अगर हम इन तीन संभावित रास्तों को समझने की करें तो पहला, धारा 17-ए को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए।दूसरा, इसे संशोधित कर सीमित रूप में लागू किया जाए। तीसरा, एक नया संतुलित मॉडल विकसित किया जाए, जिसमें, जांच की स्वतंत्रता भी बनी रहे, और ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। साथियों बातें अगर हम इस मामले परवैश्विक दृष्टिकोण- दुनियाँ क्या करती है इसको समझने की करें तो अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों में लोकसेवकों के खिलाफ जांच के लिए कार्यपालिका की पूर्व अनुमति की शर्त नहीं होती।स्वतंत्र अभियोजन और न्यायिक निगरानी को प्राथमिकता दी जाती है।यही कारण है कि वहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई संभव हो पाती है।

साथियों बात कर हम विजन 2047 और आगे का रास्ता क्या और कैसे होगा इसको समझने की करेंतो,यदि भारत वास्तव में विजन 2047 के तहत भ्रष्टाचार- मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन चाहता है, तो उसे धारा 17-ए जैसी लीकेजेस को बंद करना होगा,जांच एजेंसियों को वास्तविक स्वतंत्रता देनी होगी, और राजनीतिकइच्छाशक्ति को कानूनी ढांचे में बदलना होगा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुरक्षा और जवाबदेही का संतुलन-ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जांच को बंधक बनाना लोकतंत्र के लिए घातक है।

भ्रष्टाचार से लड़ाई में कानून को ढाल नहीं, तलवार बनना होगा। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ पर है,जिसका फैसला न केवल धारा 17-ए का भविष्य तय करेगा,बल्कि यह भी बताएगा कि भारत का लोकतंत्र 2047 की ओर किस दिशा में बढ़ेगा।, हमें बस यही सोचना है।

आईएनडीआईए की परीक्षा का साल, राष्ट्रीय राजनीति पर होगा दूरगामी असर

इस साल चार राज्यों-बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल तथा केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से तीन में आईएनडीआईए के घटक दलों की सरकारें हैं, जबकि दो में भाजपानीत राजग की। इन राज्यों की सत्ता में होने वाला बदलाव राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर डालेगा, क्योंकि विधानसभाओं के गणित से संसद के उच्च सदन राज्यसभा में संख्या बल प्रभावित होगा। इसी साल राज्यसभा की 75 सीटों के लिए भी चुनाव होने हैं। साल की शुरुआत देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनावों से हुई है। बीएमसी चुनाव में भाजपा को पहली बार जीत मिली है और ठाकरे बंधुओं-उद्धव और राज को साथ आने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा है। महत्वपूर्ण तो हर राज्य की सत्ता होती है, पर देश की निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। ग्यारह साल से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और डेढ़ दशक से बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक कटुता चरम पर है। घुसपैठ, एसआईआर और भ्रष्टाचार पर तो तकरार बरकरार है ही, आई-पैक के चेयरमैन के दफ्तर पर ईडी के छापे और उसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां पहुंच कर कुछ दस्तावेज ले जाने के बाद बंगाल की सत्ता का संघर्ष चुनाव से पहले ही सड़कों पर नजर आ रहा है। ममता इसे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर ईडी का डाका बता रही हैं तो केंद्र सरकार और भाजपा इसे सरकारी एजेंसी के कामकाज में एक मुख्यमंत्री द्वारा अवरोध डालने का अभूतपूर्व मामला बता रहे हैं। कांग्रेस और वाम मोर्चा अब बंगाल की राजनीति में हाशिये पर हैं। सत्ता की लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच है। पिछले चुनाव में खुद ममता को हरा कर भाजपा सनसनी फैलाने में तो सफल रही, लेकिन 294 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटों तक ही पहुंच पाई।

नए साल के शुरू में ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रार और उसमें संवैधानिक प्रतिमानों-परंपराओं को ताक पर रख देना बता रहा है कि साल 2026 भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इस साल चार राज्यों-बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल तथा केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से तीन में आईएनडीआईए के घटक दलों की सरकारें हैं, जबकि दो में भाजपानीत राजग की। इन राज्यों की सत्ता में होने वाला बदलाव राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर डालेगा, क्योंकि विधानसभाओं के गणित से संसद के उच्च सदन राज्यसभा में संख्या बल प्रभावित होगा। इसी साल राज्यसभा की 75 सीटों के लिए भी चुनाव होने हैं। साल की शुरुआत देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनावों से हुई है। बीएमसी चुनाव में भाजपा को पहली बार जीत मिली है और ठाकरे बंधुओं-उद्धव और राज को साथ आने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा है। महत्वपूर्ण तो हर राज्य की सत्ता होती है, पर देश की निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। ग्यारह साल से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और डेढ़ दशक से बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक कटुता चरम पर है। घुसपैठ, एसआईआर और भ्रष्टाचार पर तो तकरार बरकरार है ही, आई-पैक के चेयरमैन के दफ्तर पर ईडी के छापे और उसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां पहुंच कर कुछ दस्तावेज ले जाने के बाद बंगाल की सत्ता का संघर्ष चुनाव से पहले ही सड़कों पर नजर आ रहा है। ममता इसे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर ईडी का डाका बता रही है तो केंद्र सरकार और भाजपा इसे सरकारी एजेंसी के कामकाज में एक मुख्यमंत्री द्वारा अवरोध डालने का अभूतपूर्व मामला बता रहे हैं। कांग्रेस और वाम मोर्चा अब बंगाल की राजनीति में हाशिये पर है। सत्ता की लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच है। पिछले चुनाव में खुद ममता को हरा कर भाजपा सनसनी फैलाने में तो सफल रही, लेकिन 294 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटों तक ही पहुंच पाई। तृणमूल 215 सीटें जीत गई। तृणमूल को 48 और भाजपा को 38 प्रतिशत मत मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह फासला बढ़ गया। यही फासला तय करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। तीन कार्यकाल के बाद सत्ता विरोधी भावना स्वाभाविक है, पर ममता के 'बांग्ला अस्मिता' के मुद्दे की काट भाजपा नहीं कर पा रही। एसआईआर और घुसपैठिया विवाद के बीच अगर भाजपा बंगाल में महाराष्ट्र और बिहार की पुनरावृत्ति कर पाई तो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी दूरगामी असर होगा। दूसरा बड़ा और मुश्किल राज्य तमिलनाडु है।

वहां द्रमुक की सरकार है, जो 'इंडिया' का घटक दल है। दशकों से तमिल राजनीति द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच बंटी रही, लेकिन जयललिता के निधन के बाद परिदृश्य बदला है। अन्नाद्रमुक और अभिनेता विजय के इर्दगिर्द भाजपा चुनावी बिसात बिछाना चाहती है, पर किसी चमत्कार की खुशफहमी उसे भी नहीं है। उत्तर भारत में भाजपा की लहर चलाने वाले मुद्दे दक्षिण में अभी तक तो नहीं चले हैं। एमके स्टालिन सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना के अलावा वंशवाद, भ्रष्टाचार और हिंदी विरोध सरीखे मुद्दे भी हैं, पर उनका चुनावी लाभ उठाने के लिए विश्वसनीय विकल्प भी चाहिए। भाजपा की रणनीति फिलहाल गठबंधन के जरिये मत प्रतिशत बढ़ाने की ज्यादा लगती है। पिछले लोकसभा चुनाव में अभिनेता सुरेश गोपी के सांसद बनने और हाल में तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाने के करिश्मे के बावजूद भाजपा केरल में हाशिये पर ही है। केरल में सत्ता राजनीति वाम मोर्चा 'एलडीएफ' और कांग्रेसी मोर्चा 'यूडीएफ' के बीच बंटी है। हालांकि हर चुनाव में सरकार बदल जाने का सिलसिला पिछली बार वामपंथी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तोड़ दिया। इस बार उनके विरुद्ध ज्यादा सत्ता विरोधी भावना की उम्मीद है, पर उसका चुनावी लाभ कांग्रेस को ही मिल सकता है। अपने अंतिम दुर्ग की सत्ता से विदाई वाम राजनीति के लिए बड़ा झटका साबित होगी। वहीं असम पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का प्रवेश द्वार माना जाता है। वहां की सत्ता कब्जाने के बाद ही भाजपा का पूर्वोत्तर में विस्तार हुआ, जिसका श्रेय पूर्व कांग्रेसी हिमंता बिस्वा सरमा को जाता है। बंगाल की तरह असम में भी घुसपैठ बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिस पर आक्रामकता के साथ कांग्रेस को भाजपा घेरती रही है। कांग्रेस की सारी उम्मीदें वहां गौरव गोगोई के नेतृत्व तथा क्षेत्रीय दलों से तालमेल पर टिकी हैं। पुदुचेरी की राजनीति अक्सर तमिलनाडु की राह चलती रही है, लेकिन 2021 से वहां भाजपा समर्थित एन रंगासामी सरकार है। 30 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में 10 सीटें जीतने वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने छह सीटें जीतने वाली भाजपा के साथ मिल कर सरकार बनाई। अगर कांग्रेस और द्रमुक सत्ताविरोधी भावना का लाभ उठाते हुए आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा को दक्षिण भारत में अपना एकमात्र शेष सत्ता दुर्ग भी गंवाना पड़ सकता है। ये विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा की भावी चुनावी तैयारियों पर भी असर डालेंगे, लेकिन आईएनडीआईए का तो भविष्य ही एकता और सफलता पर निर्भर करेगा, क्योंकि चुनाव-दर-चुनाव उसमें दरारें बढ़ती जा रही हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कन्हा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582083548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। [illegible]

उदीषा चौपाला साहित्योत्सव की तैयारियां युद्ध स्तर पर

मुरादाबाद।

साहित्य-कला-संस्कृति का सशक्त हस्ताक्षर उदीषा चौपाला साहित्योत्सव-2026 की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। मुख्य संरक्षक मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह तैयारियों का जायज़ा ले चुके हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के कांधों पर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे सक्रिय रहेगी। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह को प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने टीमों का गठन भी कर दिया है। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध रहेंगी। उच्च कोटि के साहित्यकारों की पुस्तकें भी स्टाल पर उपलब्ध होगी। लोगों में किताबों के पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए बुक फेयर भी लगवाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था का दायित्व नगर निगम के कंधों पर होगा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल स्वयं पर्यवेक्षण करेंगे। उत्तरी भारत में प्रमुख स्थान बनाने जा रहा उदीषा चौपाला साहित्योत्सव (साहित्य, कला-संस्कृति को पूरी तरह

समर्पित) आगामी 22 से 26 जनवरी तक गांधी मैदान, मुरादाबाद (सर्किट हाउस के पीछे) होने जा रहा है। जिसकी तैयारियां मण्डलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह के निर्देशन में युद्ध स्तर पर जारी है। भव्य पंडाल आदि की व्यवस्था का दायित्व आबिद इलैक्ट्रिक वर्क्स के प्रोपराइटर आबिद हुसैन के कांधों पर है। उदीषा चौपाला साहित्योत्सव वास्तव में उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इवेंट माना जा रहा है। इस इवेंट की कमान स्वयं कमिश्नर आन्जनेय कुमार सिंह ने संभाल रखी है। इन पांच दिवसों में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार विश्वास कुमार शर्मा उर्फ कुमार विश्वास, सांसद मनोज तिवारी, पलक मुं छल, प्रोफेसर वसीम बरेलवी समेत देश की जानी-मानी हस्तियां प्रतिभाग करेंगी। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले नवगीतकार माहेश्वर तिवारी के नाम पर एक लाख रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया जायेगा। यह पुरस्कार इस आयोजन की विशेषता माना जा रहा है। साथ दी लोगों में किताबों के प्रति रुचि पैदा हो, इसके लिये किताबों भी प्रदर्शनी भी लगेगी।

'आदर्श जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है योग'

मुरादाबाद। चित्रगुप्त इण्टर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के ग्राम मोरा मुस्तकम में आयोजित हो रहे विशेष शिविर के द्वितीय दिवस को योग एवं उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया गया। प्रथम सत्र को योग दिवस के रूप में मनाया गया। योग प्रशिक्षक गौरव त्यागी ने बताया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं है बल्कि यह आदर्श जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। यह मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक सन्तुलन स्थापित करने में मदद करता है जिससे व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है। योग प्रशिक्षक द्वारा सभी छात्रों को विभिन्न प्रकार के योग एवं प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय सत्र में उद्यमिता एवं स्वरोजगार विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कुलदीप सिंह ने कहा कि उद्यमिता बेरोजगारी का समाधान है क्योंकि यह नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों में बदलती है, नए रोजगार के अवसर पैदा करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है, और आर्थिक विकास को गति देती है। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि वे नौकरी के भरोसे न रहकर उद्यमिता एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में उतरे। शिविर की पर्यवेक्षक डॉ निधि अग्रवाल ने कहा कि ऐसे शिविर हमें अपने आप को सामाजिक परिवेश में रहना और जीना सिखाते है साथ ही हमारी अन्तर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने में सहायक होती है।अध्यक्षता कार्यक्रम अधिकारी डॉ राजीव कुमार ने की। संचालन डॉ विशेष कुमार शर्मा ने किया।कार्यक्रम में अभय सिंह,हितेश तनिष कुमार, रितिक,शुभ वर्मा, शनि ,शिवाशु,सुहैल ,इमाद ने विशेष सहयोग किया।

नवीन नगर में श्री शकुंतला प्रकाश गुप्ता चौक का हुआ लोकार्पण

मुरादाबाद।

महानगर की शिक्षाविद स्वर्गीय शकुंतला प्रकाश गुप्त की स्मृति में आज एक भव्य समारोह में नवीन नगर चौराहे का नाम उनके नाम पर करते हुए एक शिलान्यास का लोकार्पण करते हुए नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि महानगर में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं और शहर की सूरत बदलती जा रही है। मुरादाबाद के मानसरोवर इंटर कॉलेज में श्रीमती शकुंतला गुप्ता की पुण्यतिथि पर आयोजित एक भव्य समारोह में मेयर विनोद अग्रवाल ने नवीन नगर चौराहे

का नाम शकुंतला गुप्ता चौक के सिलपटका लोकार्पण करते हुए कहा कि मुझे नगर निगम के मेयर पद पर काफी लंबा समय हो गया हम विकास की राजनीति करते हैं विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं आज महानगर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और महानगर की सूरत बदलती जा रही है उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों को बधाई दी और कहा आने वाले समय में कॉलोनी में और भाव विकास होंगे। इस अवसर पर बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष विशेष कुमार गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता जादूगर जुगनू राजेश रस्तोगी सुनीता गुप्ता क्षेत्रीय पार्षद पंकज शर्मा एवं क्षेत्र की सैकड़ो गण मान्य लोग उपस्थित है।

निजी लाइब्रेरियों पर नियंत्रण की एबीवीपी ने उठाई मांग

मुरादाबाद।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुरादाबाद महानगर द्वारा आज शहर में संचालित निजी लाइब्रेरियों की अनियमितता एवं छात्र सुरक्षा से जुड़े गंभीर विषय को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। परिषद ने अवगत कराया कि वर्तमान समय में मुरादाबाद में अनेक निजी लाइब्रेरियाँ बिना किसी प्रशासनिक अनुमति एवं स्पष्ट नियमावली के संचालित हो रही हैं, जिनमें से कई 24 गुणा 7 खुली रहती हैं। इन लाइब्रेरियों में न तो समुचित सुरक्षा व्यवस्था है

और न ही आवश्यक तकनीकी मानकों का पालन किया जा रहा है, जो विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है।

एबीवीपी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि सभी निजी लाइब्रेरियों का अनिवार्य पंजीकरण कराया जाए, 24 गुणा 7 खुली रहने वाली लाइब्रेरियों पर समय-सीमा तय की जाए तथा सीसीटीवी, अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास, महिला सुरक्षा, प्रकाश एवं वेंटिलेशन जैसे मूलभूत प्रबंध अनिवार्य किए जाएँ।

साथ ही एक मानक नियमावली बनाकर समय-समय पर प्रशासनिक निरीक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाए।महानगर मंत्री गौरव क्षत्रिय ने कहा कि, छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यदि शीघ्र ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद जनहित में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर महानगर सहमंत्री मंत्री छविनाथ अरोरा ,राजा शर्मा ,अनमोल शर्मा सचिन यादव, हर्षित गॉड ,हर्ष सक्सेना, प्रखर बंसल ,प्रतीक राघव, मोहित पाल, आशीष, शिवम ठाकुर, नवनीत कटारिया, अभिषेक, गगन, मयंक अंशु शर्मा आदि उपस्थित रहे।

ध्वस्त मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

फतेहपुर।

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा काशी के मणिकर्णिका घाट को प्रदेश सरकार द्वारा ध्वस्त कराए जाने का आरोप लगाते हुए उसके पुनर्निर्माण को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया कि उक्त मणिकर्णिका घाट सन 1791 में माता अहिल्या बाई द्वारा जीर्णोद्धारित कराया गया था एवं सनातन धर्म में उसका महत्वपूर्ण स्थान है अतः काशी के धर्माचार्यों एवं काशी वाशियो से विचार विमर्श कर उसका पुनर्निर्माण कराया जाए। ज्ञापन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों से दूर केवल धर्म स्थलों को तोड़ने का काम कर रही है, काशी का मणिकर्णिका घाट सनातन धर्म के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पर भाजपा सरकार पता नहीं कौन से सनातन धर्म को मानती है ये समझ से परे है क्यों कि सनातन धर्म गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरा नंद को संगम स्नान से रोक कर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वह केवल सरकार बनाओ धर्म का पालन करती है सनातन धर्म या किसी धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं। शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने भी धर्म स्थलों को तोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि कोई भी ऐतिहासिक धर्म स्थल नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है जिससे उन्हें अपने धर्म के महत्व की जानकारी होती है उन्हें नष्ट करना अच्छमनीय अपराध है अतः सरकार जल्द से जल्द ध्वस्त घाट का पुनर्निर्माण कराए। ज्ञापन में मुख्यरूप से वरिष्ठ नेता सुधाकर अवस्थी, शेख एजाज अहमद, कलीम उल्ला सिद्दीकी, मणि प्रकाश दुबे,प्रवक्ता ई देवी प्रकाश दुबे, पं.राम नरेश महराज, अनुराग नारायण मिश्र, आदित्य श्रीवास्तव, मनोज घायल, सहाब अली, मुन्ना भाई,राजू लोधी, नवनीत तिवारी, ब्रजेश मिश्रा, बसीर अहमद, अमर नाथ कैथल,चौधरी मोइन राइन, अजय बच्चा,राजीव श्रीवास्तव, कासिम उल्ला, रिजवान, निजामुद्दीन, आदि लोग उपस्थित रहे।

एआई को हैल्थ सेक्टर में भी बड़ी जिम्मेदारी देने को मंथन

मुरादाबाद।

सूबे सरकार के स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण, आईटी एवम् इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट- 2026 की रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेटर के प्रिंसिपल प्रो. एनके सिंह के संग-संग रेडियोडायग्नोसिस विभाग के सीनियर रेडियोलॉजिस्ट प्रो. राजुल रस्तोगी ने बतौर नोडल अधिकारी प्रतिनिधित्व किया। यह केवल एक तकनीकी संगोष्ठी नहीं थी, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व के लिए एक उ'च-स्तरीय ओरिएंटेशन था, जिसमें विस्तार से बताया गया कि कैसे एआई स्वास्थ्य प्रशासन से लेकर सीधे पेशेंट मैनेजमेंट तक सब कुछ मौलिक रूप से बदल देगा। प्रो. सिंह कहते हैं, केवल नवाचार ही हमारा लक्ष्य नहीं है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में एआई को प्रभावी बनाने के लिए, हमें सिर्फ निर्माण से आगे बढ़कर प्रमाणित परिनियोजन की ओर बढ़ना होगा। अब हम राज्य-व्यापी स्तर पर क्यूरेट किए गए, प्रामाणिक डेटा का उपयोग करते हुए मल्टी-सेंटर वैलिडेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रो. रस्तोगी कहते हैं, हम विकसित भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बतौर नोडल ऑफिसर इस यात्रा में सबसे आगे मेरा रहना टीएमयू हॉस्पिटल परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। उल्लेखनीय है, इस कॉन्फ्रेंस में वाणि'य एवम् उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवमम् सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय रा'य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम एवम् चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री ब्रजेश पाठक समेत एक दर्जन मंत्री और आला अफसरों के अलावा गूगल, नीदरलैंड के एक्सपर्ट्स की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। दो दिनी यह कॉन्फ्रेंस एलेट्स टेक्नोमीडिया के सहयोग से लखनऊ के द सेंट्रम में हुई। देशभर में हो रही आठ रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस सीरीज के तहत आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल गवर्नेंस, हेल्थकेयर इन्नोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित सार्वजनिक सेवाओं में यूपी की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें हेल्थ सिस्टम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं में एआई के रियल-टाइम उपयोग को प्रस्तुत किया गया। साथ ही सरकार, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की गई। उल्लेखनीय है, सम्मेलन से निकलने वाले सुझाव और परिणाम 16 फरवरी को होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के राष्ट्रीय रोडमैप में शामिल किए जाएंगे।

लाल किला ब्लास्ट- दूसरे आत्मघाती हमलावर की तलाश में था मास्टरमाइंड, एनआईए जांच में बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। लाल किले के पास हाल में हुए कार बम धमाके के बाद पकड़े गए सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जांच में सामने आया है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड डॉ. उमर-उन-नबी एक दूसरे आत्मघाती हमलावर की भर्ती करने की कोशिश कर रहा था. हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सका, क्योंकि संबंधित व्यक्ति ने सेब की पैदावार के मौसम में अपने परिवार की मदद करने की जरूरत का हवाला देते हुए इस आतंकी साजिश से पीछे हटने का फैसला कर लिया. अधिकारियों ने रविवार (18 जनवरी) को यह जानकारी दी. श्रीनगर पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने नबी द्वारा संचालित एक समानांतर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. नबी वही व्यक्ति था जो 10 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी गाड़ी चला रहा था. इस विस्फोट में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ के दौरान डॉक्टर से आतंकी बने व्यक्ति द्वारा अपनाई गई भर्ती की रणनीतियों का खुलासा हुआ है. इन्हीं जानकारियों के आधार पर एनआईए ने शोपियां निवासी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि नबी ने डार को एक संभावित आत्मघाती हमलावर के रूप में सफलतापूर्वक कट्टरपंथी बना दिया था, लेकिन पिछले साल अगस्त में हुई एक मुलाकात के दौरान उसने आखिरी समय में इस साजिश से पीछे हटने का फैसला किया. उसने इसके लिए सेब की पैदावार का मौसम और घर में मरम्मत का काम होने को कारण बताया. अधिकारियों के अनुसार, डार 2023 से नबी के संपर्क में था. उसने यह भी स्वीकार किया कि नबी का एक पेशेवर डॉक्टर होना उसके प्रभाव में आने का एक बड़ा कारण बना. डॉक्टर होने के कारण उसकी कट्टरपंथी बातें भर्ती किए गए लोगों को अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय लगती थीं. अधिकारियों ने बताया कि जांच से संकेत मिला है कि नबी केवल आतंकी ही नहीं था, बल्कि रणनीतिक रूप से भर्ती भी करता था. वह 'प्राइमरी सेल' के पकड़े जाने पर भी आतंकी अभियान की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सेकेंडरी, स्वतंत्र सेल बना रहा था. जांच के दौरान, पुलिस ने एक आरोपी के फोन में एक 'वॉइस नोट' भी बरामद किया, जिसमें वह जिहाद के लिए बायत (निष्ठा की कसम) ले रहा है. बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुका डार का नाम पहले भी जांच में सामने आया था, जब उसका एक दोस्त आतंकी संगठनों से जुड़ा था. अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि वह सोशल मीडिया 'टेलीग्राम' के जरिए नबी के संपर्क में था और उसे हमेशा बेहतरीन शारीरिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता था. अधिकारियों के अनुसार, डार दूसरा संभावित आत्मघाती हमलावर था, जिसे नबी इस आतंकी मॉड्यूल में शामिल करने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने बताया कि नबी कट्टरपंथी था और उसका मानना था कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आत्मघाती हमलावर का होना बेहद जरूरी है. पिछले वर्ष जब श्रीनगर पुलिस द्वारा इस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जा रहा था, तब दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से यासिर उर्फ दानिश नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था.

भारत-यूएई रिश्तों को नई रफ्तार- डिफेंस-ट्रेड समेत 9 बड़े समझौते किए

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को भारत के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। जहां पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने निवास लोक कल्याण मार्ग पर अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की उस पहल की सराहना की, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के लिए ऐतिहासिक कलाकृतियां लोथल में प्रदान की जाएंगी। दोनों देशों ने ध्रुवीय विज्ञान, संयुक्त अभियान और संस्थागत सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करने पर सहमति जताई।

पीएम मोदी ने शेख मोहम्मद को किया धन्यवाद

विक्रम मिस्री ने आगे कहा कि यूएई में लगभग 45 लाख भारतीय मूल के लोग रहते और काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का इन भारतीय नागरिकों की भलाई और हितों की देखभाल के लिए धन्यवाद किया। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन किया।

पीएम मोदी-शेख नाहयान के बीच बैठक, इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

मुलाकात में इन क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति

भारत और यूएई ने 2032 तक सालाना व्यापार 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया।
पीएम मोदी और यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच दिल्ली में अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई।
दोनों नेताओं ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर सहमति जताई।
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला, यूएई हर साल भारत को 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी देगा।
यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है।
न्यूक्लियर ऊर्जा में सहयोग पर सहमति, बड़े रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिक क्षेत्र बनाया गया, भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित होगा।
यूएई भारत में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश करेगा।
अंतरिक्ष क्षेत्र में संयुक्त सहयोग, लॉन्च पैड, सैटेलाइट निर्माण और संयुक्त मिशन पर काम होगा।
गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र विकसित करने पर समझौता।
धोलेरा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, पोर्ट, स्मार्ट सिटी और रेलइन्फ्रा परियोजनाएं विकसित होंगी।
खाद्य सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर, इससे भारतीय किसानों को फायदा होगा।
डेटा एम्बेसी स्थापित करने की संभावना पर भी चर्चा हुई।
दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
यमन, गाजा और ईरान की स्थिति पर भी बातचीत हुई।
यूएई राष्ट्रपति ने BRICS में भारत की अध्यक्षता को समर्थन दिया।

व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में भी बनी सहमति

मिस्री ने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी कई पहलें तेज करने पर सहमति बनी। इनमें भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत-अफ्रीका सेतु पहल शामिल हैं। यूएई की कंपनियों डीपी वर्ल्ड और फर्स्ट अबू धाबी बैंक को गिफ्ट सिटी, गुजरात में अपने कार्यालय और संचालन खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों ने राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफार्मों के इंटरकनेक्शन पर काम करने और व्यापार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया।

द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा

बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत-यूएई के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने कहा कि बीते एक दशक में भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। बैठक में दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में हुए उच्चस्तरीय दौरों का भी स्वागत किया। उन्होंने पिछले दो वर्षों में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भारत दौरे का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने कहा कि इन दौरों से भारत-यूएई संबंधों में पीढ़ीगत निरंतरता दिखाई देती है और यह साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी।

सुबह-सुबह दिल्ली में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

नई दिल्ली। सोमवार की सुबह दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे हड़कंप मच गया। यह घटना सुबह 8 बजकर 44 मिनट पर हुई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली में धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं, हरियाणा के सोनीपत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के कारण अब तक किसी तरह से जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप के झटके हल्के थे, किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन अचानक आए इन झटकों ने लोगों को कुछ पलों के लिए आशंकित कर दिया। कई लोगों ने अपने घरों और कार्यालयों में कंपन महसूस किया, जिसके बाद वे बाहर निकल आए।

मुंबई में बीएमसी मेयर की जंग तेज, संजय राउत बोले- होटल बना जेल, शिंदे के पार्षद हुए कैद

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सोमवार को आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने विजयी उम्मीदवारों को मुंबई के एक होटल में कैदियों की तरह कैद कर रखा है। उन्होंने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा किस बात से डर रहे हैं? शिवसेना यूबीटी सांसद की ये टिप्पणियां उनके पहले के दावों के बाद आई हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि पार्षदों में कई नए चेहरे गैर-भाजपा नेता का समर्थन कर रहे हैं।

राउत ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी भाजपा के मेयर को चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। भाजपा को पूर्ण जनादेश नहीं मिला है। शिंदे सेना के विजयी उम्मीदवारों को ताज लैंड्स एंड होटल में लगभग कैदियों की तरह रखा गया है। होटल जेल में बदल गया है। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार और एक मजबूत मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस होने के बावजूद, ये पार्षद बंद हैं। वे इतने डरे हुए क्यों हैं? मुंबई में बीएमसी महापौर पद के लिए संभावित खींचतान के बीच होटल राजनीति की वापसी के चलते, शिवसेना (यूबीटी) ने एकनाथ शिंदे पर होटलों को जेल में बदलने का आरोप लगाया है।

मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं... प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा पर पारिवारिक संबंधों को बर्बाद करने का लगाया आरोप

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव ने सोमवार को अपनी पत्नी एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता अपर्णा बिष्ट यादव पर पारिवारिक संबंधों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह जल्द ही उनसे तलाक लेंगे।

मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की

प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, ''मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक संबंधों को बर्बाद कर दिया है। वह सिर्फ नाम और दबदबा बनाना चाहती है। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और उसे कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की।

अपर्णा ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

अपर्णा से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उनके करीबी लोगों ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। प्रतीक, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे हैं। उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थीं। वह 2022 में भाजपा में शामिल हो गईं।

रायबरेली से राहुल गांधी का मनरेगा बचाओ मिशन, यूपी में 30 महापंचायतों की तैयारी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को रद्द करने के विरोध में जनसभा को संबोधित करने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। गांधी आज लखनऊ से रायबरेली के लिए सड़क मार्ग से रवाना होंगे और भुएमऊ गेस्ट हाउस में रात बिताएंगे। अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन, यानी 20 जनवरी को, राहुल गांधी रोहनिया, उन्नाव में एक एमजीएनआरईजीए चौपाल (सामुदायिक सभा) आयोजित करेंगे। राहुल गांधी आईआईटी कॉलोनी स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी रायबरेली द्वारा आयोजित प्रीमियर लीग टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी करेंगे और एमपीएलएडीएस (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) के कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे। वे नगर निगम अध्यक्ष के आवास पर भी जाएंगे।

इसके बाद, दूसरे दिन कांग्रेस सांसद की अपने गेस्ट हाउस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक निर्धारित है। कांग्रेस ने हाल ही में पारित विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 का विरोध किया है, जिसने प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना का स्थान लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को कहा कि नए कानून के विरोध में एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 महापंचायतों का आयोजन करेगी। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इनमें से कुछ महापंचायतों में भाग ले सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में, पार्टी ने केंद्र के हाल ही में पारित VB-G RAM G अधिनियम के विरोध में MGNREGA बचाओ शीर्षक से देशव्यापी तीन चरणों के आंदोलन की घोषणा की थी। पार्टी के अनुसार, अभियान का दूसरा चरण, जो 12 जनवरी को शुरू हुआ, 30 जनवरी तक चलेगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत स्तर की चौपालें आयोजित की जाएंगी और कांग्रेस अध्यक्ष का पत्र भी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पर्चे बांटने की भी योजना है। उन्होंने कहा, 30 जनवरी को, शहीद दिवस के अवसर पर, पार्टी एमजीएनआरईजीए कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगी।

किश्तवार में आतंकियों से मुठभेड़, सेना का एक हवलदार शहीद

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक सेना हवलदार शहीद हो गया। इस मुठभेड़ में आज सुबह कम से कम आठ जवान घायल हो गए। रविवार को किश्तवार के चतरू इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के खिलाफ अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुष्टि की है कि अभियान अभी भी जारी है। आतंकवाद विरोधी अभियान के आगे बढ़ने के साथ ही सुरक्षा बलों ने सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में कम से कम आठ जवान घायल हो गए। यह मुठभेड़ रविवार को किश्तवार के चतरू इलाके में शुरू हुई, जब सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के खिलाफ अभियान चलाया। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुष्टि की है कि अभियान अभी भी जारी है। आतंकवाद विरोधी अभियान के आगे बढ़ने के साथ ही सुरक्षा बलों ने सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है।

निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम नायब सहित हरियाणा से 20 पदाधिकारी बने प्रस्तावक

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को शुरू हुई चयन प्रक्रिया में कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नामांकन पत्र दाखिल करवाया। प्रस्तावकों में हरियाणा भाजपा इकाई की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित बीस पदाधिकारी शामिल हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।

इस प्रक्रिया की देखरेख पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। भाजपा के संविधान के अनुसार, किसी राज्य के निर्वाचक मंडल के कोई भी 20 सदस्य संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, जो चार कार्यकाल तक सक्रिय सदस्य रहा हो। साथ ही जिसकी सदस्यता के 15 वर्ष पूरे हो चुके हों।

पार्टी संविधान के मुताबिक ऐसा संयुक्त प्रस्ताव कम से कम पांच राज्यों से आना चाहिए जहां राष्ट्रीय परिषद के लिए चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। अधिकतर पदाधिकारी और मंत्री पहले हरियाणा भवन पहुंचे और वहां से एक साथ भाजपा मुख्यालय के रवाना हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाद में पार्टी कार्यालय पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया को लेकर सभी नेताओं में उत्साह दिखा। हर किसी ने कहा कि नितिन नवीन ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उन्हें जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी इस सोच को आगे बढ़ाया कि आने वाला समय युवाओं का है। नितिन नवीन सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में पार्टी सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि पहले रहे अध्यक्षों ने भी बेहतर काम कर पार्टी को यहां तक पहुंचाया है।

माघ मेला में विवाद: अविमुक्तेश्वरानंद बोले- पालकी से ही जाऊंगा नहाने, प्रशासन बोला- उनको नहीं मानते शंकराचार्य

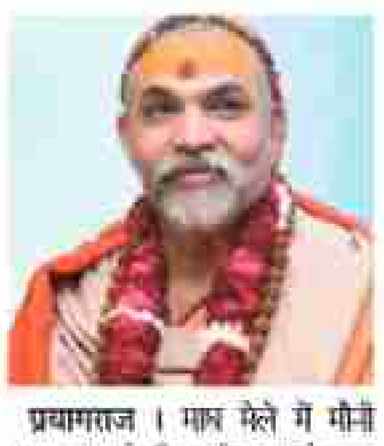

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 24 घंटे से अनशन पर बोले- प्रण लेता हूं, मेले में हर बार आऊंगा; फुटपाथ पर रहूंगा

प्रयागराज। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना के बाद धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि वह स्नान करने पालकी से ही जाएंगे और प्रशासन जब तक लिखित रूप से माफी नहीं मांग लेता वह नहीं उठेंगे।

साधु संतों को पीटा गया

उन्होंने पुलिस पर साधु संतों को पीटे जाने का आरोप लगाते हुए इस पूरी घटना के लिए पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, गृह सचिव मोहित गुप्ता और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को फोटो दिखाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है।

जहां प्रशासन ने छोड़ा वहीं विराजमान हूं

शंकराचार्य ने सीओ विनीत सिंह की फोटो दिखाते हुए आरोप लगाया कि संगम नोज पर जिन साधु संतों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उन्हें विनीत सिंह ने पीट-पीट कर घायल किया। शंकराचार्य ने कहा कि वह धरने पर नहीं बैठे हैं। प्रशासन उन्हें जहां छोड़ गया था वह वहीं विराजमान हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि माघ मेले में संगम स्नान के लिए चारों शंकराचार्य के लिए प्रोटोकॉल बनना चाहिए ताकि शंकराचार्य पालकी पर जाकर स्नान कर सकें।

मेला प्रशासन नहीं मानता उन्हें शंकराचार्य

कमिशनर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि किसी को भी गंगा स्नान से नहीं रोका गया। मेला प्रशासन उनको शंकराचार्य नहीं मानता।

उन्नाव पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का मामला: हाईकोर्ट का कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक से इनकार

नई दिल्ली। वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित करने की मांग वाली पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया। इससे पहले दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

पिता की हिरासत में मौत मामले में 10 साल की सजा देने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही

कोर्ट में सोमवार (19 जनवरी) को सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया। इससे पहले दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। पिता की हिरासत में मौत मामले में 10 साल की सजा देने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सेंगर को अपील याचिका पर निर्णय में आने में देरी की वजह उनके द्वारा दाखिल की गई कई अर्जियां हैं। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पांच केसों का ट्रायल, जिसमें पीड़िता के पिता की मौत से जुड़ा केस भी शामिल था, उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। दिसंबर 2019 में सेंगर को रेप का दोषी पाया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उसे पीड़िता के पिता की मौत की साजिश रचने का भी दोषी ठहराया गया था और जून 2024 में हाईकोर्ट ने मामले में उसकी सजा निलंबित करने की अपील खारिज कर दी थी।